धैन सिंह और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य

10 अगस्त, 2004

(के. जी. बालकृष्णन और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे. जे.)

दंड संहिता, 1860:

धारा 304- बी और 201-दहेज मृत्यु-दुल्हन की जलने की चोटों से मृत्यु उसकी शादी के वर्षों बाद-घायल को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया-मृतक के रिश्तेदारों और पुलिस को सूचित किए बिना शव का संयोजन किया गया-दोषसिद्धि दहेज; और यह कि कथित के बीच निकट संबंध होना चाहिए क्रूरता और मृतक की मृत्यु-आयोजित, यह साबित होता है कि मृतक की मृत्यु हो गई जलने की चोटों के लिए और यह सामान्य परिस्थितियों में नहीं था और यह कि पति ने उत्पीड़न किया-धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम के तहत पति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता था और उसे उचित रूप से आरोपित अपराधों-साक्ष्य अधिनियम, 1872 का दोषी ठहराया गया था। 113- बी.

धारा 201-दहेज मृत्यु-घायल को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया-दाह संस्कार मृतक के रिश्तेदारों और पुलिस को सूचित किए बिना विवाह-

दोषसिद्धि-आरोपी, मृतक के पति के चाचा, यह अनुरोध करते हुए कि केवल दाह संस्कार में भागीदारी यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि उसने अन्तर्गत धारा 201 का अपराध किया था- आयोजित साक्ष्य से पता चलता है कि सब कुछ गुप्त और गुप्त तरीके से किया गया था और परिस्थितियों से पता चलता है कि आरोपी शव के गुप्त निपटान में पक्षकार था-इसलिए ज्ञान हो सकता है उसे जिम्मेदार ठहराया गया कि वह अच्छी तरह से जानता था कि एक अपराध किया गया था और उसने सबूतों को गायब कर दिया था-धारा 201 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने में कोई अवैधता नहीं है।

पलविंदर कौर बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर (1952) एस. सी. 354

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 5/2004

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 1989 के आपराधिक अपील संख्या 495-एस. बी. के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से कुलदिप सिंह और राज के. पांडे।

उत्तरदाता की ओर से अरुण के. सिन्हा, राकेश सिंह और सुश्री नरेश बख्शी।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया:

अपीलार्थी दोषसिद्धि और पारित सजा के आदेश को चुनौती देते हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की। प्रथम अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 304-बी और 201 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे दस साल के कठोर कारावास और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई गई दो साल की अवधि के लिए।

यह घटना 13.10.1988 पर हुई। शिंदर कौर की बेटी पीडब्लू-2 की शादी उनकी मृत्यु से लगभग ढाई साल पहले पहली अपीलार्थी धैन सिंह से हुई थी। शादी के बाद शिंदर कौर उनके साथ रहीं। पति लगभग एक वर्ष के लिए। यह आरोप लगाया गया था कि पहली अपीलकर्ता, पति, अधिक दहेज चाहता था और उसे परेशान करने लगा इसलिए उसने उसे छोड़ दिया वैवाहिक घर और अपने आश्रितों के साथ रहने लगी। इसके बाद स्थानीय पंचायतदारों के हस्तक्षेप से एक समझौता किया गया और अपनी मृत्यु से दो महीने पहले, उसने अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया और फिर से काम करना शुरू कर दिया अपीलार्थी धैन सिंह के साथ रहना। पीडब्लू-2 को पता चला कि उनकी बेटी शिंदर कौर को जला दिया गया है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी ने शव का अंतिम संस्कार 13.10.1988 पर ही कर दिया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू-1 से पीडब्लू-8 की जांच की गई और रक्षा पक्ष डी. डब्ल्यू.-1 तारा सिंह से पूछताछ की गई। सत्र अदालत ने माना कि मृतक शिंदर कौर की मौत जलने से हुई थी और पहली अपीलकर्ता ध्यान सिंह दहेज की मांग के कारण क्रूरता के लिए जिम्मेदार था और इस प्रकार आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपराध किया। सबसे पहले अपीलार्थी को भी अपराध करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था -आईपीसी की धारा 201।

निर्णय 2004 अनुपूरक(3) एससीआर 442 न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गयाः

अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला द्वारा उनके खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी, जिसकी पुष्टि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने की थी। पहले अपीलकर्ता को धारा 304-बी और 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और क्रमशः दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। दूसरे अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी पाया गया और दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

घटना 13.10.1988 को घटित हुई। पीडब्लू-2 की बेटी शिंदर कौर की शादी उसकी मृत्यु से लगभग ढाई साल पहले पहले अपीलकर्ता धैन सिंह से

हुई थी। शादी के बाद शिंदर कौर करीब एक साल तक अपने पति के साथ रहीं। यह आरोप लगाया गया कि पहली अपीलकर्ता, पति, अधिक दहेज चाहता था और उसे परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। फिर स्थानीय पंचायतदारों के हस्तक्षेप पर एक समझौता हुआ और अपनी मृत्यु से लगभग दो महीने पहले, उसने अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया और फिर से अपीलकर्ता धैन सिंह के साथ रहने लगी। 22.10.1988 को पीडब्लू-2 को पता चला कि उनकी बेटी शिन्दर कौर को जलाकर मार दिया गया है। वह तुरंत थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू-1 से पीडब्लू-8 तक की जांच की गई और बचाव पक्ष की ओर से डीडब्ल्यू-1 तारा सिंह की जांच की गई। सत्र न्यायालय ने माना कि मृतक शिंदर कौर की मृत्यु नितंब की चोटों से हुई और पहला अपीलकर्ता ध्यान सिंह दहेज की मांग के कारण क्रूरता के लिए जिम्मेदार था और इस प्रकार आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध किया। प्रथम अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील और प्रतिवादी के वकील को सुना।

अपीलकर्ता के वकील ने हमारे सामने आग्रह किया कि यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है कि पहले अपीलकर्ता ने कभी

पीडब्लू-2 से किसी दहेज की मांग की थी। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि पहले अपीलकर्ता की ओर से कोई क्रूरता थी। अपीलार्थी का तर्क सही नहीं है। पीडब्लू-2 ने इस आशय का साक्ष्य दिया कि अपीलकर्ता ने दहेज की मांग की थी और उसने टेलीविजन सेट की मांग की थी और पीडब्लू-2 उसे नहीं दे सका और इसलिए मृतक को उसके माता-पिता के घर वापस भेज दिया गया। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृतका ने पति का घर छोड़ दिया क्योंकि वह उसके घर में दयनीय जीवन सहन नहीं कर सकती थी और विवाद को सुलझाने के लिए एक पंचायत भी हुई थी। माना जा रहा है कि मृतक शिंदर कौर की मौत जलने से हुई है। धारा 304-बी दहेज मृत्यु को परिभाषित करती है और इसमें कहा गया है कि एक महिला की मृत्यु किसी जलने या गंभीर चोट के कारण होती है या उसकी शादी के सात साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न या दहेज की किसी मांग के संबंध में, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। मौजूदा मामले में, यह साबित हो गया है कि उसकी मौत जलने से हुई थी और यह सामान्य परिस्थितियों में नहीं थी। सबूतों से यह भी पता चलता है कि पति ने उत्पीड़न किया,

इसलिए वह उसके साथ वैवाहिक घर में नहीं रह सकी और अपने माता-पिता के साथ रहने लगी।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों में इस आशय का अनुमान लगाने में सक्षम बनाती है कि, जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसी महिला की हत्या कर दी गई थी। ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न या दहेज की किसी मांग के संबंध में, ऐसे व्यक्ति को दहेज हत्या का कारण माना जाएगा।

अपीलकर्ता के वकील का तर्क यह है कि भले ही यह साबित हो जाए कि दहेज की मांग के कारण क्रूरता हुई थी, ऐसी क्रूरता मृत्यु से ठीक पहले होगी और कथित क्रूरता और मृतक की मृत्यु के बीच निकटतम संबंध होना चाहिए। यह सच है कि अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि क्रूरता और आत्महत्या के बीच संबंध होना चाहिए और बरती गई क्रूरता ने पीड़ित को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया होगा। अपीलकर्ता के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसके आत्महत्या करने का कोई अन्य कारण था। साक्ष्य से पता चलता है कि पहले अपीलकर्ता ने दहेज की मांग की थी और उसने उसे अपने घर से दूर भेज दिया था और मध्यस्थता के बाद ही उसे अपीलकर्ता के घर वापस ले जाया गया और उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। ये तथ्य स्पष्ट रूप से

दर्शाते हैं कि आत्महत्या मृतक के साथ हुई प्रताड़ना या क्रूरता का परिणाम थी। के अंतर्गत अनुमान अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी लागू की जा सकती है और सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 304-बी आईपीसी और धारा 201 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया।

दूसरा अपीलकर्ता प्रथम अपीलकर्ता का चाचा है। सबूतों को गायब करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें दोषी पाया गया। इस अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने मृतक शिंदर कौर के शव का अंतिम संस्कार करने में मदद की थी।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि शव के दाह संस्कार में शामिल होना ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने आईपीसी की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध किया है। यह तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि एक अपराध किया गया है और अभियुक्त को पता था या उसके पास विश्वास करने का कारण था कि ऐसा अपराध आवश्यक ज्ञान के साथ और इरादे से किया गया था । अपराधी को कानूनी सज़ा से बचाना उसके सबूतों को गायब कर देता है या गलत जानकारी देता है।

पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1952) एससी 354- अदालत ने माना कि यह दिखाने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता को पता था कि अपराध किया गया था और कोई प्रत्यक्ष परिस्थितिजन्य सबूत नहीं था जो कि सामग्री को साबित करने के लिए आवश्यक था। अपराध। मौजूदा मामले में चौंकाने वाले तथ्यों पर गौर किया जाए तो शिंदर कौर की 13.10.1988 को जलने से मौत हो गई। वह स्वीकारोक्तिपूर्वक प्रथम अपीलकर्ता के साथ रह रही थी। पहले अपीलकर्ता के अनुसार जब शिन्दर कौर जलकर घायल हुई तो वह अपने घर में नहीं था। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जांच में, वह घायल शिंदर कौर को अस्पताल ले गए थे। लेकिन मामले में बचाव पक्ष के गवाह ने बताया कि शिंदर कौर को शुरू में एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया और उनके निर्देशों के अनुसार उसे दूसरे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पहले अपीलकर्ता ने मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी और पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरा अपीलकर्ता प्रथम अपीलकर्ता के निवास के निकट रहता था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मृतक के पिता पीडब्लू-2 ने इस आशय का साक्ष्य दिया कि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में बिल्कुल भी सूचित नहीं किया गया था और उन्हें पीडब्लू-6, मुख्तियार सिंह के माध्यम से उसकी मृत्यु के बारे में पता चला। प्रथम अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दाह संस्कार स्थल पर पीडब्लू-2 और उसके रिश्तेदारों सहित

लगभग 50 व्यक्ति थे। यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी सबूत नहीं है कि दाह संस्कार पीडब्लू-2 या मृतक के किसी करीबी रिश्तेदार की उपस्थिति में किया गया था। घटना के बारे में पीडब्लू-2 और पुलिस को सूचित करने में विफलता और यह तथ्य कि घायल को किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था, यह दर्शाता है कि सब कुछ गुप्त और गुप्त तरीके से किया गया था और मामले की परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि दूसरा अपीलकर्ता रहस्य का पक्ष था। शव का निपटान. इसलिए, उसे इस ज्ञान का श्रेय दिया जा सकता है कि वह अच्छी तरह से जानता था कि एक अपराध किया गया था और उसने सबूतों को गायब कर दिया। हमें दूसरे अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में कोई अवैधता नहीं मिली धारा 201 आईपीसी. अपीलकर्ता संख्या 2 को इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी और उसे केवल एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा काटनी पड़ी थी। सजा की शेष अवधि काटने के लिए उसे अपने जमानत बांड के साथ आत्मसमर्पण करना होगा।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पुलकित शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।